IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण की गुणवत्ता और रोजगार : युवाओं पर प्रभाव का अध्ययन

पूर्णिमा कौषिक
षोधार्थी षिक्षा संकाय
आई एस बी एम विष्वविघालय गरियाबंद

डॉ. सिद्वेष्वर मिश्रा
षोध निर्देषक षिक्षा संकाय
आई एस बी एम विष्वविघालय गरियाबंद

ABSTRACT:

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई भारत सरकार की एक अग्रणी परिणामोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण योजना है। इस कौशल प्रमाण और पुरस्कार योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं की दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना तथा जुटाना है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके और अपने आजीविका का अर्जन कर सके। देश में विशेषता युवा के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाय तो ग्रामीण विकास साधा जा सकता है भारत सरकार का केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इस हेतु विशेष प्रयास कर रहा है। केंद्रीय बजट में इसके लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास से लाभांति ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी ग्रामीण विकास में कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

KEYWORDS: ग्रामीण विकास कौशल विकास योजना प्रशिक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास ही राष्ट्र की प्रकृति का आधार हो सकता है। ग्रामों की संपन्नता और समृद्धता ही देश की अर्थव्यवस्था को सही मायने में सशक्त बना सकती है देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा हिस्सा है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहना उचित होगा। देश की ग्रामीण भागों का बड़ा योगदान होता है। ग्रामीण विकास के लिए गांव में रोजगार सृजन करने के लिए स्थानीय युवा वर्ग को रोजगार प्रदान करना आवश्यक है। देश की बेरोजगारी की अर्थव्यवस्था चिंताजनक है। बेरोजगारी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। कुशल श्रमिक एवं श्रम शक्ति है जिससे मानव संसाधन कहते हैं ग्रामीण युवा वर्ग को कुशल मानव संसाधन बनाने के लिए सरकारी प्रयासों का अवलोकन आवश्यक है। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा वर्ग को रोजगार की दृष्टि से कुशल बनाना प्रशिक्षित करना उन में उद्यमिता विकसित करना प्रत्येक सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रस्तुत कौशल विकास योजना का अध्ययन करना है जिससे भविष्य में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसरों में वृद्धि हो सके। कौशल से आशय ऐसे ज्ञान और क्षमता से है जो किसी कार्य को करने में विशेषता प्रदान करती है।

रोजगार प्राप्ति में कुशलता आवश्यक है कौशल विकास से आशय व्यक्ति में विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट निपुणता योग्यता एवं क्षमता को विकसित करने के लिए ज्ञान एवं प्रशिक्षण दोनों की प्रक्रिया है।

योजना आयोग के अनुसार ऐसे भौगोलिक भाग जहां की जनसंख्या 15000 से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। नेशनल सैंपल सर्विलाइजेशन के अनुसार ग्रामीण भाग वह है

1. जहां की जनसंख्या 400 वर्ग किलोमीटर में बसी हो
2. उसे भाग की सीमा निश्चित हो
3. जहां की कम से कम 75% पुरुष जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्रित हो

सरकारी योजना और उसकी आवश्यकता

कौशल विकास वर्तमान केंद्रीय सरकार के महत्व कांची योजना है। कौशल भारत के उद्देश्य

1. कौशल विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण करना।
2. व्यावसायिक कुशलता तथा रोजगार अनुकूल प्रशिक्षण देना।
3. कुशल मानव संसाधन श्रम शक्ति का निर्माण करना।

सरकार का केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास कार्यक्रम और कुशल भारत अभियान के लिए उत्तरदायित्व है।

इस योजना की अपेक्षा है युवा वर्ग की शक्ति और कौशल का उपयोग केवल स्थानी और राष्ट्र श्रम बाजार तक ही सीमित ना हो बल्कि अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार में भी उनकी मांग हो जिसके लिए उनमें योग्यता क्षमता एवं कुशलता का विकास करना आवश्यक है। भारत कुशलता की राजधानी बने ग्रामीण विकास में कौशल विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा आई इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार प्रयत्नशील है। कौशल विकास योजना और कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण भागों में काफी संभावनाएं और क्षमताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि की जा सकती है। निर्यात वस्तुओं के निर्माण में इस योजना और कार्यक्रमों से कौशल विकास होगा विशेषता ग्रामीण क्षेत्र से हस्तकला कुटीर उद्योग हस्तोद्योग कपड़ा निर्माण पेड़ पौधों से औषधि निर्माण आदि का अंतरराष्ट्रीय निर्यात किया जा सकता है। इसके लिए किए गए पर्यटन यशस्वी होते दिख रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम से रोजगार निर्माण होगा जिसके लिए कौशल विकास परख सिद्ध होगा। भारत सरकार ने रोजगार सृजन के लिए विदेशी कंपनियों के आगमन को आकर्षित करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों और प्रावधानों को उदार बनाया है। इससे देश में कुशल श्रमिक शक्ति का उपयोग बढ़ेगा उनकी आय में वृद्धि होगी जो देश के कवज बढ़ाने में सहायक होगी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का प्रतिशत 5 से अधिक है। बढ़ती बेरोजगारी गंभीर समस्या की चेतावनी दे रही है। विश्व के सबसे युवा देश जहां दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की संख्या को वहां उनका रोजगार न मिल पाना युवा शक्ति एवं क्षमता का व्यय होना है युवा वर्ग की अधिक आबादी जहां देश के लिए वरदान है वही इनका उपयोग नहीं होने पर या देश के लिए अभिशाप बन जाएगी, इस दृष्टि से कौशल भारत योजना अत्यंत प्रासंगिक और उपयोगी सिद्ध होगी। अब इसकी सफलता और यश के लिए सरकारी गैर सरकारी प्रयत्नों की अत्यंत आवश्यकता है

शोध क्षेत्र

किसी भी शोध अध्ययन के व्यवस्थित अध्ययन के लिए उसके क्षेत्र का निर्वहन भी करना चाहिए। क्षेत्र का निर्धारण आवश्यक और उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। यदि शोध का क्षेत्र छोटा होगा तो हो सकता है कि वह शोध अध्ययन के निष्कर्ष से काफी दूर हो जाय। अर्थात निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं रह जाते और यदि सोच क्षेत्र व्यापक हो तो इस समय और श्रम की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तथा आर्थिक साधन भी बहुत अधिक खर्च करने पड़ते हैं।

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ जिले को लिया गया है। छत्तीसगढ़, जिले में उत्खनन के कारण घनत्व है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़, जिले की जनसंख्या 2,088,928 है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात 990 है। इसका तात्पर्य है की कुल जनसंख्या 2,470,996 मैं पुरुषों की संख्या 1,259,628 एवं महिलाओं की संख्या 1,211,368 है। छत्तीसगढ़ , जिले में जनसंख्या का घनत्व 135 व्यक्ति प्रगति वर्ग किलोमीटर है छत्तीसगढ़ , जिले में राज्य की कुल जनसंख्या का 4.9 प्रतिशत भाग रहा है। वर्ष 2011 की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत जिले में 28.29 प्रतिशत है एवं साक्षरता दर 74.38 प्रतिशत है।

पूर्व शोध की समीक्षा

कौशल विकास योजना के संबंध में अनेक शोधार्थियों द्वारा किया गया है। किंतु लगभग सभी शोधार्थियों ने कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन उनके परिणामों आने वाली समस्या एवं समाधान के उपायों पर गणना से अध्ययन नहीं किया प्रस्तावित शोध अध्ययन में कौशल विकास योजना का रोजगार के अवसर के सीजन में योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर वास्तविक परिणाम को जानने का प्रयास किया जाएगा एवं समाधान के उपायों पर भी विस्तृत प्रकाश डाला जाएगा।

पटेल और निमिषा शाह 2019 में अपने अध्ययन में रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की। वैश्वीकरण के तकनीकी शिक्षा के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। आगे सबसे बड़ी चुनौती का कॉरपोरेट जगत को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की आपूर्ति करना था। स्नातक स्तर के छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और भर्ती हुई तकनीक के ज्ञान की कमी है और इसलिए उन्होंने तेजी से बदलते परिवेश में रोजगार में कठिनाइयों का सामना किया। व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा टज्म , कौशल और शिक्षार्थियों की दक्षता विकसित की जानी है। भारत में बेरोजगारी अनुपात में खतरनाक अनुपात हासिल कर लिया है। इसके अलावा, उद्देश्य शैक्षिक अवसरों के लिए विविधीकरण के लिए प्रदान करना है, व्यक्तिगत रोजगार की क्षमता को बढ़ाना और कुशल श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना है।

श्रीवास्तव 2020 में कहां है की उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के कारण, तीसरी दुनिया के देशों में उच्च शिक्षा हाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत में अधिकांश छात्र उच्च अध्ययन के लिए और विदेशी भाषा कौशल में सुधार करने और अवसरों को प्राप्त करने के लिए विदेश जा रहे हैं। व्यवसाय से संबंधित ज्ञान और कौशल के साथ बड़ी संख्या में उच्च विद्यालयों का विस्तार करना आवश्यक है। लेखक ने आगे तर्क दिया है कि राष्ट्र के रोजगार योग्य कौशल को बढ़ाने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। यह वैश्विक स्तर पर छात्रों की नौकरी, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण के लिए उपयोगी और संस्थाओं और अनुसंधानों के बीच आदान-प्रदान और जुड़वा, पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों के अंतरराष्ट्रीय विपणन में वृद्धि, पूरे

देश में शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोगी के लिए स्थापना तंत्र बनाई गई है। इसलिए, ऐसा लगता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली अन्य देशों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने और साझेदारी बनाने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा रही है।

जैन 2021 ने कहां है कि भारत में उच्च शिक्षा का निजीकरण और शैक्षिक प्रणाली जीवंत लोकतंत्र की मांगों को पूरा करती है और इसे व्यापार के बजाय सामाजिक सेवा माना जाता है। इस प्रकार, तकनीकी रोजगार उन्मुक्त पाठ्यक्रमों के लिए विकास की मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने निजी संस्थाओं को शिक्षा क्षेत्र में आने की अनुमति देने और शिक्षा में अधिक नीचे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कहा और निजी प्रणाली बेहतर प्रबंधन के लिए मदद कर सकती है। लेकिन, निजीकरण लाभ के उद्देश्य की ओर निजी संस्कृत लाएगा और यह महंगा होगा जहां फीस का भुगतान गरीब छात्रों द्वारा नहीं किया जा सकता है तो, उच्च शिक्षा केवल अमीर और उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित होगी

दिव्याथोमूर्ति 2022 ने स्पष्ट किया है कि गांधीवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे व्यक्ति को बाद के जीवन में स्वावलंबी बनने में मदद मिल सकें । इसके अलावा, सच्ची शिक्षा को अज्ञानता और अंधविश्वास से छात्रों को साक्षर करना चाहिए और स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के गुण की खेती करनी चाहिए। अंत में, लेखक का निष्कर्ष है कि शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा है और इसका मतलब न केवल व्यक्ति विकास, बल्कि विकास अर्थव्यवस्था भी है।

चंद्र बोस 2023 ने बताया है कि शैक्षिक प्रणाली में सुधार जैसे की सामग्री इकट्ठी और उत्कृष्टता पाठ्यक्रम के विभिन्न अंग के रूप में कौशल प्रशिक्षण बनाने की आवश्यकता होगी। शिक्षा के संबंध में वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण घटक उच्च गुणवता वाली जनशक्ति के उत्पादन की आवश्यकता है जो दुनिया के बाजारों में सफलतापूर्वक प्रति स्पर्धा का सामना कर सकता है। इस प्रकार, फैंसी कारण का शिक्षा प्रणाली का एक बहु आयामी प्रभाव है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए विशेष संदर्भ के साथ शैक्षिक प्रणाली में सुधारो की आवश्यकता को रेखांकित किया है। अंत में, अंतरक्षेत्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव लाने से संबंधित विवादों को भी जन्म दिया है, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के डाउनमिडिज्ड नीति और आने वाली पीढियां के लिए छात्रों की वैश्विक शिक्षा बाजार में किसी भी विचारहीन प्रवेश के लिए अग्रणी है।

शोध प्रविधि

शोध या अन्वेषण किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है। ज्ञान की किसी भी शाखा में ध्यान पूर्वक नए तथ्यों की खोज के लिए किए गए अन्वेषण या परिक्षण को अध्ययन कहते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है

शोध कार्य में कौशल विकास योजना का रोजगार के अवसर के सृजन में योगदान से संबंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों को एकत्र कर पूर्ण किया गया है । प्राथमिक आंकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोत ऑन में एकत्र किए गए। जबकि द्वितीयक आंकड़े कौशल विकास योजना का रोजगार सीजन में योगदान की समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित पुस्तकें, शोध पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शासकीय प्रतिवेदनों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, एवं इंटरनेट आदि का भी आंकड़े एवं विषय वस्तु से संबंधित स्टडी मैटेरियल एकत्र करने में प्रयोग किया गया है।

शोध उद्देश्य

इस मुख्य उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, भारत सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजना के कार्यन्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कॉमन नाम्र्स 4 के अनुसार पूरे देश में युवाओं के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। योजना के तहत दिए जाने वाले पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क छैफथ, के अनुरूप है। कौशल विकास योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार है।

1. राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मोर्चे में शिक्षित बेरोजगारी की बुराइयों को जानना

2. भारत में कौशल विकास योजना की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।

3. छत्तीसगढ़ जिले में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन या कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए रोजगार सृजन आए और परिसंपत्ति निर्माण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना

4. जिले में लाभार्थियों के पुनभुगतान व्यवहार की जांच करना।

5. कौशल विकास योजना के लाभार्थियों की अपेक्षाओं का अध्ययन करना। जहां तक भविष्य में कौशल विकास योजना का आकार है।

6. क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को सामाजिक जनसंख्यिकी विशेषताओं का अध्ययन करना।

7. पूर्व गृह के प्रति ग्रामीण युवाओं के दृष्टिकोण के स्तर का आकलन करना।

8. विभिन्न पुनर्योजी अवसरों के बारे में जागरूकता के स्तर की पहचान करना।

9. उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विश्लेषण और युक्त करना और ग्रामीण युवाओं के विकास में विभिन्न संगठनों की भूमिका की जांच करना।

10. छत्तीसगढ़, क्षेत्र के संभावित क्षेत्रों में सूचना उद्यमिता के लिए व्यवसाय योजना का विकास करना।

11. वर्तमान एवं उभरती हुई बाजार आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक की उच्च गुणवता वाला कुशल कार्य बल विकसित करना

12. सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं तथा लाभ वंचित समूह के लिए जीवन प्रयत्न कौशल प्राप्त करने हेतु अवसरों का सृजन करना।

13. कौशल विकास पहलुओं की अंगीकार करने में सभी हिट धारा को की वचनबद्धता को बढ़ावा देना।

14. उद्योग डिजाइन किए गए गुणवंता कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को सक्षम करना ताकि युवा रोजगार परख बने और अपनी आजीविका अर्जित करें।

15. मौजूदा कार्यबल उत्पादकता में वृद्धि, और देश की वास्तविक जरूरत के साथ कौशल प्रशिक्षण संरेखित करना।

16. प्रमाणन प्रक्रिया के माननीय कारण के को प्रोत्साहित करें और कौशल की एक रजिस्ट्री बनाने के लिए न्यू रखें।

17. 6 साल (2016-2022) की अवधि में 10 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करें।

18. हितधारको (stakeholders) की आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को विशेषताओं के प्रत्युत्तर में लोचशील वितरण तंत्रो की स्थापना करना।

19. विभिन्न मंत्रालयों, केंद्र तथा राज्य एवं सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं के मध्य प्रभावी समन्वय संभव बनाना।

शोध परिकल्पनाएं

कौशल विकास योजना के कथित उद्देश्यों और अध्ययन के खिलाफ निम्नलिखित परिकल्पना प्रासंगिक है।

जो तैयार की गई है। शीर्षक से संबंधित शोधार्थियों की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित है-

* योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो रहा है

* किस ग्रहण के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हो रहा है।

* वर्तमान वित्तीय प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

* छत्तीसगढ़, जिले में योजनान्तर्गत विकास हो रहा है।

* योजनाओं में लक्ष्य एवं प्राप्ति के अनुपात में अंतर है।

* रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है।

* लाभार्थियों के रोजगार और आए पर कौशल विकास योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

* निम्न आय के बचाए उच्च गतिविधि आय लाभार्थियों को नियमित रूप से रन किसको को चुकाने के लिए प्रेरित करती है।

* कौशल विकास योजना का प्रभाव वैसा नहीं है जैसा कि उद्योग, सेवाओं और व्यावसायिक क्षेत्र के बीच है।

* कौशल विकास योजना का रोजगार के अवसरों के सीजन में योगदान आमतौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में खराब और गैर सम्मान है।

कौशल विकास और बजट

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का बजट वर्ष 2017-18 में विगत बजट से 2.5 गुना अधिक राशि खर्च करके 17,000 करोड रुपए रहा है। वर्ष 2018-19 में 2820 करोड रुपए था, वर्तमान वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 2989 करोड रुपए किया गया है। बजट से संबंधित कौशल विकास के सरकारी प्रयास इस प्रकार है

कौशल विकास और बजट

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का बजट वर्ष 2017-18 में विगत बजट से 2.5 गुना अधिक राशि खर्च करके 17,000 करोड रुपए रहा है। वर्ष 2018-19 में 2820 करोड रुपए था, वर्तमान वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 2989 करोड रुपए किया गया है। बजट से संबंधित कौशल विकास के सरकारी प्रयास इस प्रकार है

1. प्रधानमंत्री कौशल केंद्र,(PMIKK) का वर्तमान में 60 जिलों में संचालन हो रहा है जिससे 600 जिलों में आरंभ करने की योजना है।

2. देश में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र आरंभ करना जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देना तथा विदेशी भाषा सीखने की व्यवस्था करना

3. संकल्प (SNKALAP Acquisition and knowledge Awareness for Livelihood promotion programme) आरंभ करना जिसके लिए 4000 करोड रुपए व्यय किए जाएंगे। जिसमें बाजार संबंधित अनुकूल प्रशिक्षण देना 3.5 करोड़ी युवाओं को लाभांति करना ।

4. औद्योगिक मूल्य विस्तार के लिए कौशल सशक्तिकरण STRIVE (skill stainghtening वित Industrial value Enhancement) का दूसरा चरण लागू करना जिसके लिए पैसा करोड रुपए की लागत होगी। इसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गुणवंता वृद्धि एवं बाजार प्रासंगिकता के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। इससे युवा वर्ग की कुशलता में वृद्धि होगी और उद्योगों को कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध होगी।

5. चमड़ा, जूते चप्पल तथा कपड़ा उद्योग में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनायी है। कपड़ा उद्योग का देश में रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र कृषि के पश्चात है जहां 33.35 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। जिसे इस योजना के तहत 2022 तक बढ़कर 60.62 ग्रामीण मिलियन रोजगार महिया करने का लक्ष्य है।

6. ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के प्रसार के लिए 4500 करोड रुपए का आवंटन किया है।

7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP(PM's employment generation programme) के बजट में तीन गुना अधिक राशि का प्रावधान करना, जिससे कुशल मानव संसाधन का उपयोग किया जा सके।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए मिस्त्री कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक प्रशिक्षण देना।

9. तकनीकी विकास करना जिससे नव युवा वर्ग को नया स्टार्टअप करने में सहायता करना।

10. अति बिगवान ब्रांडेड की सुविधा 1.5 लाख गांव तक पहुंचाना।

इसके अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आजीविका योजना है, जो कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने से पहल कर रही है। जिसका उद्देश्य है, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के युवाओं को विशिष्ट ज्ञान और कौशल प्रदान करना जो उन्हें शीघ्र रोजगार दे सके। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1500 करोड रुपए का प्रति वर्ष प्रावधान छंत्स्ड छंजपवद ततंस स्पअमसपीववक डपेपवदद्ध मैं किया है जिससे गरीबों की रेखा के नीचे युवाओं में कुशलता के विभिन्न प्रशिक्षण दिए जायेंगा । कल 73 कौशल विकास की योजनाएं भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा अमल में लाई जा रही है।

समस्याएं

1. कुशल मानव संसाधन का अभाव-

जहां निर्माण कार्य शुरू है वहां कुशल बढाई, वेल्डर इलेक्ट्रिशियन का अभाव है, विभिन्न औद्योगिक, इकाइयों में जैसे गोदाम और लाॅजिस्टिक फेब्रिकेशन आदि में कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या कम है।

2. कार्य संस्कृति का अभाव-

विभिन्न औद्योगिक इकाइयां अपने मानव संसाधनों से जिस प्रकार की कार्य संस्कृति(work Cultural) की अपेक्षा रखतीं है, वहां उन्हें श्रमिकों में दिखाई नहीं देती है।

3. आकर्षक औद्योगिक नीति का अभाव-

कुशल मानव संसाधनों को उद्योग ही रोजगार देते हैं, किंतु उद्यमी और प्रबंधन या महसूस करते हैं कि जिले के लिए औद्योगिक नीति अपने मित्रता पूर्ण और अनुकूल अथवा प्रोत्साहन पूरक नहीं है।

4. उचित परिश्रमी का अभाव-

कुशल श्रम शक्ति के लिए पारिश्रमिक कम होने की शिकायत कुशल श्रमिक करते दिखायी देते हैं।

5. काम देने वाले और काम मांगने वाले की कडी के बीच खड़ी अभाव-

कुशल मानव संसाधन एवं औद्योगिक इकाई को जोड़ने वाली रोजगार विनिमय कार्यलय (employment exchange centre) उल्टा सुस्त ढीला है।

रोजगार निर्माण करने वाले अन्य विभिन्न क्षेत्र वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, खाद्य संस्करण, सूचना व तकनीकी(IT) रेडीमेड कपड़े, हॉस्पिटैलिटी, संचार माध्यम, यातायात आदि जिले में कार्यरतहै, जहां कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकार की समस्या संपूर्ण देश में व्याप्त है।

सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिकार अधिक आसान निर्माण किए जाने चाहिए।
2. अधिकार अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित एवं लाभांति करना चाहिए।
3. कुशल एवं प्रशिक्षित लोगों के वास्तविक आंकड़ों की जानकारी मंत्रालय में होनी चाहिए।
4. कौशल केदो की गतिविधियों की अधिकतम प्रभावी बनाना चाहिए।
5. सरकारी बजट का ईमानदारी से उपयोग एवं पूर्व व्यय किया जाना चाहिए।
6. युवा वर्ग को कौशल विकास के आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
7. विशेषता आधुनिक तकनीकी जानकारी एवं उसका उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जायें।
8. निजी उद्यमियों को प्रत्येक जिलों में उधम एवं व्यवसायिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सरकारी सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाय।
9. लैंगिक समानता के सिद्धांत के अनुसार युवा वतियों एवं महिलाओं को कौशल विकास के अवसर अधिक प्रदान किया जायें।
10. विद्यालयीन स्तर पर कौशल आधारित आधारभूत अभ्यास क्रम से संबंधित शिक्षा तथा विषयो से इसे शामिल किया जायें

11. प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी युवाओं का अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाए।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई आरंभ करने व उद्यमियों के लिए कड़े सरकारी नियम व प्रधानों को उधर बनाना चाहिए।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवा वर्ग को नौकरी से प्राथमिकता एवं अधिक स्थान देनी चाहिए।

14. कौशल विकास प्रशिक्षणार्थीयों सरकार द्वारा स्कॉलरशिप इस स्टाय फंड देना चाहिए।

15. प्रत्येक प्रशिक्षणाथियों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण का महत्व संबंधी जानकारी दी जाय।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल और संसाधनों का उपयोग के तरीकों की जानकारी दी जाये।

17. कौशल विकास प्राप्त व्यक्तियों को उसके काम का उचित पारिश्रमिक दिया जाए।

18. कुशल व्यक्ति द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध करना एवं उचित प्रदान किए जाएं।

19. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अन्य मंत्रालय द्वारा कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए बनाई गई सभी योजनाएं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में संबंध भूमिका निभाकर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

20. कुशल व्यक्ति द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए देश भर में विक्रय की व्यवस्था निर्माण हो।

21. वस्तुएं निर्यात करने के लिए सरकारी एजेंसी ने मध्यस्थ की भूमिका निभानाचाहिए।

निष्कर्ष

कौशल विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएंहैं, इसके लिए विशेष मंत्रालय बनाया गया है। बजट में हर वर्ष बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है। युवा भारत को रोजगार निभाने में कौशल विकास ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सकता है। सरकार केंद्र ग्रामीण विकास और रोजगार उपलब्ध कराने में गति लाने के साथ निजी व्यावसायिक संस्थानों के प्रयासों की भी आवश्यकता है। कौशल विकास और उद्यमिता में एकात्मकता लाने की सरकार का प्रयत्नप्रशासनीय है। किंतु वास्तविक रूप से इस योजना को लागू करने की राह में परंपरागत सोच, अधिकारियों की उदासिनता, भ्रष्टाचार केवल विज्ञापन की अधिकता, बड़ी बाधा है, अन्यथा यह योजना का सफल होना युवा शक्ति का शानदार उपयोग होगा जो युवा वर्ग की क्षमतावान, समथयवान बनाने के साथ उन्हें जीविकोपार्जन साधन उपलब्ध करायेगा, जो देश की आय वृद्धि में प्रमुख साधन बनेगा।

संदर्भ

1. डॉ. बी .एल . गुप्ता. सांख्यिकी साहित्य भवन पब्लिशर्स डिस्ट्रन्यूटर्स 2005
2. डॉ डी.एन चतुर्वेदी डॉ पी. सी. सिन्हा, आर्थिक शोध के तल, लोग भारतीय प्रकाशन 1979
3. कटरिया रस्तागी, सांख्यिकी सिद्धान्त एवं व्यवहार पब्लिकेशन मेरठ 1988-89
4. एस.के. मिश्रा बी.के. पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस 2007
5. शर्मा वीरेन्द्र प्रकाश, रिसर्च मेथडोलांजी, पंचशील प्रकाशन जयपुर 2004
6. आर.ए. दुबे, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशर्य हाउस नई दिल्ली
7. जैन, डॉ . एम.के., शोध विधियाँ, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2006
8. डॉ.चतुर्भुज मामोरिया भारत की आर्थिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूट्स 207-08

9. डॉ ओ.पी. शर्मा, भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण, रामप्रसाद एण्ड संस 2002-03
10. छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र. 2017-18
11. छत्तीसगढ़ की आधारभूत कृषि सांख्यिकी आयुक्त, भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त, म.प्र. ग्वालियर 2011
12. उद्यमी, उद्योग और स्वरोजगार - चतुर्थ संस्करण उद्यमिता केन्द्र म.प्र 2009
13. उद्यमी, उद्योग और स्वरोजगार - चतुर्थ संस्करण उद्यमिता केन्द्र म.प्र 2009
14. भारत की जनगणना - जनसंख्या के अनंतिम आंकड़े, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2001
15. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, छत्तीसगढ़